विकास के साथ आम आदमी का दर्द

(पृष्ठ एक का शेष) नहीं होगा और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति वह चाहे कितना भी प्रभावशाली हो छोड़ा नहीं जाएगा और बेकसूर को नाजायज़ तंग नहीं किया जाएगा।

सरकार ने अपने विकास प्रयासों में आम आदमी की बेहतरी का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रदेश के सभी गाँव जब सड़कों से जुड़ जाएंगे तो निःसंदेह लोगों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आएगा। विकास के रास्ते खुलेंगे और प्रदेश निरंतर विकसित होगा। लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा युवाओं को उच्च तकनीकी और विशेषज्ञ शिक्षा हासिल करने के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

सरकार ने हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अतिरिक्त सैंकड़ों करोड़ो के वित्तीय लाभ दिए हैं। उनकी सेवा शर्तों को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया है। मज़दूरों की दिहाड़ी को पहले 75 रुपये से 100 रुपये करना और एक वर्ष बाद उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि करना गरीब लोगों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 200 रुपये से 330 रुपये बढ़ाकर समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति सरकार ने अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। हज़ारों दैनिक भोगी एवं अनुबंध पर लगे कर्मचारी नियमित हुए हैं।

कृषि पैदावार में विविधता लाकर सरकार ने किसानों-बागबानों की आर्थिकी को सुदृढ़ कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है। पॉली हाऊस के निर्माण तथा सिंचाई सुविधा के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान देना निःसंदेह एक सराहनीय कदम है। इससे गरीब किसान भी नई तकनीक अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे और बेहतर आमदनी हासिल कर सकेंगे। समर्थन मूल्य देने के साथ-साथ इस साल से आम और सेब को फसल बीमा योजना के अतंर्गत लाकर कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के खराब होने के कारण जो उनकी आर्थिकी चरमरा जाती थी, उससे राहत मिलेगी।

साधनों के सृजन की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि सरकार जानती है कि जब तक प्रदेश में आय के साधन नहीं होंगे, तब तक विकास की गति को तेज़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता तथा औद्योगिक विकास एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2012 तक प्रदेश में जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य यानी 10 हजार मेगावाट निर्धारित किया गया है, वह सराहनीय है, क्योंकि इससे प्रदेश को करोड़ो रुपये की आय होगी। साथ ही उद्योगों एवं अन्य गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त एवं सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, जिससे यहाँ निवेश बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रदेश को आय भी होगी। यही स्वरोज़गार, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान का मूल मंत्र है और सरकार का ध्येय भी।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में भी सराहनीय प्रगति हुई है। शीघ्र ही 400 करोड़ रुपये की लागत से एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के प्रयास जारी है, जिसमें लगभग 25 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया है। इससे भी सूचना प्रौद्योगिकी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास में विशेष महत्व है।

प्रदेश में पॉलिथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर इस प्रदेश ने अन्य राज्यों को रास्ता दिखाया है। आज अन्य राज्य में भी इस ओर ध्यान दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह प्रदेश अग्रणी रहा है। हिमालयी राज्यों की शिमला में दो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित कर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक पहल की है। प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है और इस क्षेत्र में यह प्रदेश देश में डायमंड स्टेट के रूप में उभरा है।

प्रदेश सरकार ने विकास को जो गति दी है, उसमें मानवीय स्वरूप का विशेष ध्यान रखा गया है। सामाजिक सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित हो रही कुल योजना की 11 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 25 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकाधिक लोग लाभान्वित होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए अनेक अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है। वह चाहे स्वरोज़गार की हो, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की हो या अन्य सभी का ध्येय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का तीव्र उत्थान सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर भी विशेष बल दिया गया है।

सरकार का दो वर्ष का शासनकाल निःसंदेह उपलब्धियों भरा, प्रदेश के तीव्र विकास एवं आम आदमी की बेहतरी की दिशा में किए गए प्रयास का रहा है और सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, उनके दूरगामी परिणाम प्रदेश के तीव्र विकास एवं जन कल्याण के हित में है और प्रदेश के स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

प्रमुख उपलब्धियां

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये की गई। 27757 नये पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत। 2,52,048 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।
- दैनिकभोगियों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये की गई। प्रत्येक दिहाड़ीदार श्रमिक को 12775 रुपये का वार्षिक लाभ।
- 31 मार्च 2009 तक 8 वर्ष पूरे कर चुके दिहाड़ीदार एवं अनुबन्ध के आधार पर रखे गए कर्मियों को नियमित करने के निर्देश। 28 हजार से अधिक कर्मी लाभान्वित।
- प्रदेश के कर्मचारियों को सितम्बर, 2009 से पंजाब के अनुरूप पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू।
- प्रदेश में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 353 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी 'पंडित दीनदयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना' शुरू। इस योजना के तहत किसानों को पालीहाउसों के निर्माण तथा सिंचाई प्रणाली इत्यादि को लगाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान।
- प्रदेश में 300 करोड़ रुपये लागत की 'दूध गंगा योजना' का शुभारंभ, जिसके तहत 10,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के तहत दुग्ध उत्पादन गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक की ऋण सुविधा का प्रावधान।
- महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने में प्रदेश अग्रणी।
- फलों को समर्थन मूल्य देने के साथ-साथ इस वर्ष से सेब एवं आम को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2009-10 से पूरे प्रदेश में आरम्भ। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 2,98,291 परिवारों को 30 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा छत्र प्रदान। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
- गत दो वर्षों में 449 ऐलोपैथिक व 85 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति कर दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती। इतने ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियमितीकरण प्रक्रिया जारी। नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सैकड़ों पद भरे गए।

अर्जित पुरस्कार

- प्रतिष्ठित पत्रिका 'इंडिया टूडे' द्वारा राज्यों की कार्य प्रणाली पर किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश सात मानकों में सर्वश्रेष्ठ रह कर सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाला देश का पहला राज्य।
- सर्वेक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश तथा मैक्रो इकोनॉमी में हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ। ओवर ऑल परफारमेंस, पूंजी निवेश तथा मैक्रो इकोनॉमी में फास्टेस्ट मूवर स्टेट घोषित।
- हिमाचल प्रदेश को आई.बी.एन.-7 द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा रोजगार सृजन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए 'डायमण्ड स्टेट अवार्ड'। समग्र कार्य-निष्पादन के लिए विशेष पुरस्कार।
- हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण में वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में 'डायमण्ड स्टेट अवार्ड'।
- हिमाचल प्रदेश ई-गवर्नेंस के लिए देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित।
- ई-गवर्नेंस में हिमाचल के ई-गजट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय अवार्ड।

- मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत बीमा लाभ में चार गुणा वृद्धि।
- शिमला, सोलन तथा हमीरपुर जिलों के लिए एस.एम.एस. गेटवे सर्विस का शुभारम्भ।
- शिक्षा में एक नई क्रांति का सूत्रपात। प्रदेश में 16 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना।
- तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय।
- हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत् हिमालयी विकास पर शिमला घोषणा पत्र जारी।
- प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित हो रही औद्योगिक, विद्युत एवं अन्य इकाइयों में 70 प्रतिशत पद हिमाचलियों से भरने का सैद्धांतिक निर्णय।
- स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 4800 रुपये प्रतिमाह तथा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं एवं अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि 3000 रुपये प्रति माह की गई।

हमारा संकल्प : कुशल, स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन

(पृष्ठ एक का शेष)

चाहे वे किसी भी सरकारी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग के अंतर्गत कार्यरत हैं, को प्रसूति अवकाश दिया है, उनको रक्षा बंधन और भैया दूज के दिन अवकाश के अलावा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है। इसी प्रकार गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए मातृ शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में चार गुणा वृद्धि की है। अब मृत्यु की अवस्था में एक लाख तथा गम्भीर घायल अवस्था में 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राशि में वृद्धि की गई है तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

गिरिराज: युवाओं के हित में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं?

मुख्य मंत्री : सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय तो हमने यह लिया कि जितने भी प्रोफेशनल तथा व्यावसायिक पद हैं, उनमें 50 प्रतिशत पद बैच की वरियता के आधार पर भरे जाएंगे। इससे उन युवाओं को लाभ हो रहा है, जिनको किसी कारण नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हमने इस अवधि में 25 हजार से अधिक पदों को भरने तथा सृजित करने की स्वीकृति दी है तथा निजी क्षेत्र में जैसे औद्योगीकरण, पर्यटन एवं विद्युत उत्पादन में स्थानीय लोगों को रोज़गार के हजारों अवसर सुनिश्चित किए हैं। निजी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित किया जा रहा है।

गिरिराज : दो वर्ष पूरा होने पर आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मुख्य मंत्री : सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश की तमाम जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके भरपूर सहयोग से ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। उनकी अपनी सरकार के दो वर्ष के सफल कार्यकाल पर बधाई भी देना चाहूँगा और उनसे विनम्र आग्रह भी करना चाहूँगा कि जो स्नेह एवं आशीर्वाद उनका गत दो वर्षों में मिला है, वह आगे भी मिलता रहेगा।